

अनुदान संख्या 97 - इस्पात मंत्रालय
GRANT No. 97 - MINISTRY OF STEEL

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	67,98,00		
		67,99,00	50,41,92	-17,57,08
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			17,56,68
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-	2,17,00	1,45,37	-71,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			71,61

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत बचतें हुईं:-

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head: -

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"			
उद्योग	Industries			
मू.	O.	2651.00		
पू.	S.	1.00	1237.32	1237.30
पु.	R.	-1414.68		-0.02

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹1.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(II) “इंजीनियरिंग उद्योग – परिवहन उपकरण उद्योग – भारत में व्यापारी जहाजों का ध्वज-स्थापन” के अंतर्गत – ₹886.03 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; तथा

(III) “सामान्य – अनुसंधान और विकास – लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की योजना” के अंतर्गत – ₹705.70 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती के कारण हुईं।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) Under “Engineering Industries - Transport Equipment Industries - Flagging of Merchant Ships in India” - saving of ₹886.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs); and

(III) Under “General - Research and Development - Scheme for Promotion of Research and Development in Iron and Steel Sector” - saving of ₹705.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.